विकास के नाम पर गाँव को गंदगी तोहफे के रूप मे दी गयी

घरौंडा (सोनम) विधानसभा के गाँव अलिपुरा में लोगों को गंदगी का सामना करना पड़ रहा है जिससे उनका गाँव में रहना दुश्वार हो गया है। गाँव के स्थानीय लोगों ने बताया की गाँव को विकास के नाम पर गंदगी तोहफे के रूप मे दी गयी है। स्थानीय लोगों ने बताया की गाँव में हर जगह गंदे पानी और कुड़े के ढेर जमा हो चुके है। जिससे गाँव में कई तरह की बीमारियों के पैदा होने का डर बना रहता है। इस गाँव में पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही सफाई के लिए कोई विशेष प्रबंध है।

इसी समस्या को लेकर गाँव वालों की मुलाक़ात कई बार घरौंडा के विधायक से हो चुकी ही लेकिन केवल आश्वाशन के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अब गाँव के लोग इस गंदगी से काफी परेशान है और इस समस्या से मुक्ति चाहते हैं क्योंकि गाँव के लोग इससे कई बार बीमार भी हो चुके हैं। यहाँ के लोगों की एक ही मांग है कि हमारे गाँव को स्वछ बनाया जाए और गन्दे पानी की निकासी के प्रबंध किए जाएं। तांकि गांव वासी गम्भीर बीमारियों से बच सकें।

सफेद हाथी बना कल्पना चावला मेडिकल कालेज : त्रिलोचन सिंह

करनाल (ममो)। कांग्रेस के जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह ने स्थानीय कल्पना चावला मेडिकल कालेज अव्यवस्थाओं के चलते चर्चा में है। हुड्डा सरकार के समय 800 करोड़ रुपए की लागत से कालेज का निर्माण करवाया गया था। खेद की बात है कि यह कालेज अब सफेद हाथी बन कर रह गया है।

मेडिकल कालेज डाक्टरों की कमी से जूझ रहा है। आधुनिक मशीनों की किल्लत है और जो मशीनरी उपलब्ध हैं उन्हें चलाने के लिए डाक्टर और कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। रेडियोलॉजिस्ट न होने की वजह से अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन और एमआरआई मशीन धूल फांक रही है। त्रिलोचन सिंह ने कहा कि कल्पना चावला मेडिकल कालेज में आने वाले लोगों को इलाज के नाम पर तंग होना पड़ता है। अमरजेंसी में आने वाले मरीजों को ज्यादातर रेफर कर दिया जाता है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कल्पना चावला के नाम को भी बदनाम करने का काम किया है। रोजाना मीडिया में कल्पना चावला मेडिकल कालेज की विफलता का मुद्दा छाया रहता है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज क्या सो रहे हैं? सीएम मनोहर लाल के विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं लचर हो गई हैं। कोरोना महामारी ने फिर से दस्तक दे दी है। इसकी रोकथाम के लिए भी सरकार ने कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार जनता को बचाने की बजाए उन्हें मरने के लिए छोड़ रही है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे सिर्फ खोखले नारे बनकर रह गए : सुमिता सिंह

करनाल। सुमिता सिंह पूर्व विधायक करनाल ने हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष रेनू भाटिया ने लड़कियों को लेकर विवादित टिप्पणी ओयो रूम में लड़कियां हनुमान की आरती करने नहीं जाती है की घोर निंदा की उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती है वह तो सिर्फ नारे ही बनकर रह गए रेनू भाटिया वह अन्य भाजपा नेताओं के बयान से महिलाओं के प्रति उनकी मानसिकता दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि रेनू भाटिया महिला आयोग अध्यक्ष जैसे अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है भाजपा सरकार को रेनू भाटिया को उनके पद से जल्द से जल्द बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के महिला निर्भर नहीं है वह हर मामले में आत्मनिर्भर और स्वतंत्रता और पुरुषों के बराबर सब कुछ करने में सक्षम भी है हमें महिलाओं का सम्मान जेंडर के कारण नहीं बल्कि उनकी पहचान के लिए करना होगा हमें यह स्वीकार करना होगा कि घर और समाज की बेहतरी के लिए पुरुष और महिला दोनों समान रूप से योगदान करते हैं यह जीवन को लाने वाली महिला है हर महिला विशेष होती है चाहे वह घर पर हो या ऑफिस में।

"श्रम क़ानूनों के बारे में हरियाणा सरकार अपना रुख स्पष्ट करे" मंत्री के दफ़्तर पर, लखानी के मज़दूरों की ललकार

सत्यवीर सिंह

गुस्से में तिलमिलाए लखानी के मज़दूर, यूँ तो, लखानियों की किसी ना किसी फैक्ट्री में, हर रोज़ ही चीखते- चिल्लाते रहते हैं, लेकिन वह स्वतःस्फूर्त आक्रोश होता है, दो-चार घंटे में तूफ़ान गुज़र जाता है. शातिर मालिक उससे निबटना जानते हैं; फिर कोई तारीख दे देते हैं, मज़दूरों के बक़ाया वेतन, ओवरटाइम, बोनस, ग्रेचुटी, पी एफ के उनके बक़ाया के भुगतान की. 'लखानी मज़दूर संघर्ष समिति' के बैनर तले संगठित होकर, संघर्ष का जो सुसंगठित अभियान, मज़दूरों ने इस बार छेड़ा है, वह पहली बार हुआ है. लखानी मालिक, श्रम क़ानून लागू कराने के लिए ज़िम्मेदार सरकारी विभाग और सरकार के साथ-साथ फ़रीदाबाद के जन-मानस तक इन मज़दूरों की चीख़ें पहुँचने लगी हैं.

'मज़दूर मोर्चा' के पिछले अंक की रिपोर्ट, 'लखानी के मज़दूर, देश के श्रम क़ानून लागू कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं; उनका साथ दीजिए' के अनुरूप, संघर्ष की शुरुआत करते हुए, 16 अप्रैल को, चिलचिलाती धूप की परवाह ना करते हुए, महिलाओं सहित भारी तादाद में लखानी के मज़दूर, सुबह 10 बजे, YMCA चौक पर इकठ्ठा होना शुरू हो गए थे. मौके पर लोकल मीडिया और मज़दूर यूनियनों के नेता भी प्रभावशाली रूप में मौजूद थे. बड़खल क्षेत्र के 7 दिहाड़ी मज़दूर, जिन्हें हर रोज़, अपना श्रम बेचने के लिए अनखीर लेबर चौक पर खड़ा होना होता है, अपनी दिहाड़ी की परवाह ना कर, लखानी के

संघर्षरत कामरेडों का साथ देने के लिए मोर्चे में मौजूद थे. बैनर, तख्तियां, लाल झंडे थामे, ज़ोरदार नारे लगाता, मजदूरों का जत्था 11.30 बजे, सेक्टर 8 स्थित, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के दफ़्तर पहुंचा.

मंत्री महोदय को कार्यक्रम की जानकारी होने के बावजूद, उसी वक़्त उन्हें किसी 'बहुत ज़रूरी' काम से बाहर जाना पड़ा!! फ़रीदाबाद की 19 लाख की आबादी में 60 प्रतिशत तादाद औद्योगिक मज़दूरों की है. मतलब, इन्हीं मज़दूरों के वोट से विधायक और माननीय मंत्री बने, शर्मा जी के स्टाफ और पुलिस की संवेदनहीनता ने मज़दूरों के क्रोध में घी का काम किया, जब जला डालने वाली गर्मी में, उन्हें बाहर सड़क पर ही रोक दिया गया, जबकि दूसरी ओर, तीन मंज़िला दफ़्तर और साइड के बगीचे में मंत्री जी के 'अपने' लोगों का जमावड़ा छाँव में आराम- फर्मा था. गर्मी ने सभा का तापमान बढ़ा दिया था. सबसे पहले, सीटू के जिला महासचिव कॉमरेड वी एस डंगवाल और जिला अध्यक्ष एन के पाराशर ने अपने विचार रखते हुए, लखानी के बहादुर मज़दूरों की न्याय की लड़ाई को अपना पूर्ण समर्थन, एकजुटता और संयुक्त आन्दोलन चलाने का भरोसा दिलाया.

सभा का संचालन करते हुए, क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा के अध्यक्ष कॉमरेड नरेश और मुख्य वक्तव्य रखते हुए, महासचिव कॉमरेड सत्यवीर सिंह ने, लखानी के मज़दूरों के पिछले

शेष पेज छह पर

दुनिया की बेहतरीन चिकित्सा स्कीम ईएसआईसी का भारत में हो रहा सत्यानाश

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

भारत के केन्द्रीय श्रम मंत्री भूपेन्द्र सिंह यादव खुद कह चुके हैं कि ईएसआई कॉर्पोरेशन दुनियां की बेहतरीन चिकित्सा स्कीम है; इसके बावजूद भारत में स्कीम का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। मज़दूरों से पैसे की तो भरपूर वसूली हो रही है लेकिन चिकित्सा के नाम पर ठेंगा दिखाया जा रहा है।

भारत में ईएसआई कॉर्पोरेशन द्वारा चिकित्सा सेवा देने की दो पद्धतियां है, एक तो सीधे कॉर्पोरेशन द्वारा तथा दूसरे राज्य सरकारों के माध्यम से सेवायें उपलब्ध कराना। पहली पद्धति में अस्पतालों का संचालन खुद कार्पोरेशन करता है जबकि दूसरी पद्धति में राज्य सरकारों के माध्यम से सेवायें उपलब्ध कराई जाती हैं। इस पद्धति में कुल खर्च का केवल आठवां भाग राज्य सरकार वहन करती हैं। यानी कि कुल खर्च यदि आठ रुपये है तो सात रुपये कॉर्पोरेशन तथा एक रुपया राज्य सरकार का होता है इसके अलावा इमारत एवं तमाम इन्फ्रास्ट्रक्चर भी कॉर्पोरेशन ही उपलब्ध कराता है।

देश भर में 51 अस्पताल कॉर्पोरेशन स्वयं चलाता है तथा 103 अस्पताल राज्य सरकारों द्वारा चलाये जाते हैं। कॉर्पोरेशन के 51 अस्पतालों में कुल 12 हजार 705 बेड मरीज़ों के लिये बनाये गये हैं। इनमें से केवल 9 हजार 678 बेड ही चालू हैं यानी कि उन पर मरीजों को लिटाया जा सकता है। मतलब स्पष्ट है कि बिल्डिंग व ढांचा तो 12 हजार 705 बेड का खड़ा कर दिया गया लेकिन मरीजों की सेवा के लिये केवल 9 हजार 678 बेड ही रखे गये। इस पर भी गजब यह है कि इन चालू बेड में से भी 50 प्रतिशत बेड ही भरे रहते हैं। इसका मतलब कदापि यह नहीं निकालना चाहिये कि मरीजों को इससे अधिक बेड की जरूरत ही नहीं है। समझने वाली बात यह है कि मरीज तभी अस्पताल में आकर भर्ती होगा जब उसे वहां कुछ इलाज एवं सुविधा मिलेगी अन्यथा मरने के लिये कोई क्यों आकर भर्ती होगा?

इन 51 अस्पतालों में से आठ ऐसे भी हैं जिनके साथ मेडिकल कॉलेज भी जुड़े हैं और दो ऐसे हैं जिनमें केवल पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है। इन दो में से एक दिल्ली स्थित बसइ दारापुर है जहां केवल 59 प्रतिशत बेड भरे हैं। तथा दूसरा बाम्बे में है जहां केवल 33 प्रतिशत बेड भरे हैं। मेडिकल कॉलेजों के साथ जुड़े फ़रीदाबाद व हैदराबाद के अस्पताल ही बेहतर स्थिति में है जहां न केवल शत प्रतिशत बेड भरे हैं बल्कि अतिरिक्त बेड भी लगाने पड़ रहे हैं। फ़रीदाबाद के इस अस्पताल की बेहतरीन सेवाओं को देखते हुए मरीजों की संख्या इस कदर बढती चली गई कि 300 बेड से शुरू होने वाला यह अस्पताल अब 900 बेड का हो चुका है। इतना ही नहीं 500 बेड का एक और अतिरिक्त भवन बनाने की योजना पर चर्चा बीते एक वर्ष से चल रही है।

दिल्ली के रोहिणी तथा ओखला के 300 बेड वाले अस्पतालों में क्रमशः 72 व 60 प्रतिशत बेड ही भरे रहते हैं। दिल्ली के यह अस्पताल पूर्णतया कार्पोरेशन द्वारा संचालित होने के बावजूद बहुत बेहतर सेवाये देने में असमर्थ हैं। दिल्ली से बड़ी संख्या में मरीजों को फ़रीदाबाद रेफर तो किया जा रहा है लेकिन बढते कार्य भार से निपटने के लिये आवश्यक पैरामेडिकल स्टाफ़ आदि को नहीं बढाया जा रहा। इसकी वजह से यहां की सेवायें भी बूरी तरह से प्रभावित हो रही हैं जिसे लेकर फ़रीदाबाद के मज़दूरों में रोष बढता जा रहा है।

कॉर्पोरेशन के इन 51 अस्पतालों के लिये 6 हजार 231 डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं लेकिन केवल 4082 पदों पर ही डॉक्टर नियुक्त हैं। यानी कि 2200 से अधिक डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं जबकि देश में न तो डॉक्टरों की कमी है और न ही कॉर्पोरेशन में मज़दूरों द्वारा दिये गये पैसे की। कमी है तो केवल कॉर्पोरेशन के सिर पर कुंडली मारे बैठे अफसरशाहों व राजनेताओं की इच्छाशक्ति की।

संदर्भवश सुधी पाठक जान लें कि ईएसआई कॉर्पोरेशन मुख्यालय में लगे डिसप्ले बोर्ड पर प्रत्येक अस्पताल में होने वाले इलाज तथा भर्ती एवं डिस्चार्ज का आंकड़ा ऑनलाइन प्रदर्शित होता रहता है। यानी कि कार्पोरेशन में बैठे निठल्ले अफसर पूरे देश भर में फैले अपने तमाम अस्पतालों के आंकड़े को निहारते तो रहते हैं परन्तु वे इस पर विचार करने की कतई कोई जरूरत नहीं समझते कि बेड खाली क्यों पड़े हैं, मरीज़ क्यों नहीं आ रहे? विचार करने की जरूरत ही क्या है जब उन्हें पता है कि न तो पर्याप्त डॉक्टर न ही अन्य स्टाफ़ और न ही आवश्यक उपकरण व साजो सामान।

चिकित्सा क्षेत्र में ईएसआई कॉर्पोरेशन की महत्व एवं सामर्थ्य को समझने वाले माननीय केन्द्रीय श्रममंत्री भूपेन्द्र सिंह यादव पर सवाल तो बनता ही है कि क्या उन्हें ईएसआई की यह सारी दुर्दशा नजर नहीं आ रही? यदि सब कुछ निकम्मे नालायक एवं हरामखोर अफसरों ने ही करना है तो मंत्री जी आप यहां किस लिये बैठे हैं?